

राष्ट्रपिताकोनमन...

दूसरों पर आरोप लगाने से पहले, स्वयं को परखना चाहिए।

सांध्य दैनिक

इंदौर संकेत

dainikindoresanket24@gmail.com

इंदौर, गुरुवार 09 अक्टूबर 2025

वर्ष : 4 अंक : 282 पृष्ठ : 6 मूल्य : 2

2 वसुधैव कुटुम्बकम् भारत की परम्परा रही है - परमार



इंदौर संकेत प्रतिनिधि
भोपाल • मध्यप्रदेश का औषधि प्रशासन विभाग का अमला कितना सुस्त, लापरवाह और नाकारा है, ये छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई 23 बच्चों की मौतों के मामले से साफ हो गया है। इस विभाग की लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है, दो साल पहले भी कफ सिरप 'नेचर कोल्ड' की वजह से मध्य प्रदेश की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी।
ये कफ सिरप इंदौर की सांवेर रोड स्थित रिमैन लैब्स में बनाया गया था और इसकी वजह से मध्य अफ्रीका के कैमरून शहर में 12 बच्चों की मौत

हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार से इस पर कार्रवाई के लिए कहा था। द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) की टीम ने इंदौर की रिमैन लैब्स को सील कर ड्रग लाइसेंस निलंबित कर दिया था।
स्टेट और सेंट्रल लैब कोलकाता से सैंपल फेल होने के बावजूद मध्यप्रदेश के खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने लैब पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उसी लाइसेंस पर इंदौर में दूसरी जगह फैक्ट्री खुल गई। अफसरों ने दो साल तक इस मामले को दबाया। अब छिंदवाड़ा में 23 बच्चों की मौत के बाद

5 वूमंस वर्ल्ड कप - आज जीत की हैट्रिक को उतरेगा भारत

6 भगवानों की मूर्तियों पर थूकने से भड़के बजरंगी

दो साल पहले भी इंदौर की रिमैन लैब का सिरप हुआ था बैन

अफसरों की मेहरबानी, निलंबित लायसेंस को फिर से दी अनुमति

डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के बाद फैक्ट्री सील

डब्ल्यूएचओ की सूचना के बाद भारत सरकार के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की टीम इंदौर के सांवेर रोड पर चल रही रिमैन लैब्स पर पहुंची। टीम ने यहां से कफ सिरप के सैंपल लिए गए। उन्हें भोपाल की राज्य स्तरीय लैब में जांच के लिए भेजा। यहां दवा के सैंपल फेल हो गए। रिमैन लैब्स की तरफ से इस जांच को चुनौती दी गई। सैंपल फिर से जांच के लिए कोलकाता की सेंट्रल ड्रग लैब भेज दिए गए। यहां भी जांच में दवा में घातक रसायन डायएथिलिन ग्लायकोल की मात्रा 26 प्रतिशत से ज्यादा मिली। डब्ल्यूएचओ के मानक के अनुसार डीईजी की मात्रा 0.10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

आनन फानन में 8 अक्टूबर को रिमैन लैब्स के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कराया गया था।
संचालक ने उसी लाइसेंस पर दूसरी फैक्ट्री खोल ली-इस पूरे मामले में

अफसरों की भूमिका सवाल के घेरे में है। नियम के मुताबिक, इस मामले में दवा बनाने वाली लैब के संचालक के खिलाफ एफआईआर और कोर्ट में केस दायर होना चाहिए था मगर, इंदौर के

अफसरों की गड़बड़ी की शिकायत भोपाल पहुंची

ये सवाल भी उठा कि लैब को इतनी जल्दी दूसरी जगह पर फैक्ट्री का लाइसेंस कैसे मिल गया? तो ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी के मनमोहन मोलासरिया ने कहा कि फैक्ट्री को लाइसेंस नई शर्तों पर दिया गया है। वहीं, फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से भी अफसरों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न भी लगे। फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने की शिकायत इसी साल जून के महीने में भोपाल पहुंची। इसके बाद 30 जुलाई 2025 को प्रदेश के तत्कालीन ड्रग कंट्रोलर दिनेश मोर्य ने इंदौर के वरिष्ठ औषधि नियंत्रक राजेश जीनवाल को लिखित निर्देश दिया कि दवा बनाने वाली कंपनी रिमैन लैब्स के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराए।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने फाइल दबा दी।
इतना ही नहीं, सांवेर रोड की फैक्ट्री सील होने के बाद फैक्ट्री संचालक ने साल भर के भीतर इसी

रिमैन लैब्स नाम से ही 175/2/3, मुंडला दोस्दार, कपेल रोड पर दूसरी फैक्ट्री शुरू कर दी। इसका लाइसेंस नंबर वही 28/8/91 था, जो पहले निलंबित कर दिया गया था।

ब्रेकिंग न्यूज

- आज महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव, कई कार्यक्रम में लेंगे भाग
- सत्ता में आते ही पीडीए के संत और समाज को भूल जाती है सपा - मायावती
- तेलंगाना सरकार ने रेलाइफ और रेस्पिफ्रेश टीआर सिरप किया बैन
- बरेली : एक लाख के इनामी बदमाश इफ्तिखार को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में किया डेर
- राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षामंत्री के साथ की बैठक, रक्षा सहयोग की समीक्षा की
- दिल्ली पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी
- बिहार चुनाव : आज जारी होगी जन सुराज के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट
- मुंबई : वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

कांग्रेस संगठन में बदलाव की बयार जिलाध्यक्ष के बाद बदले जिला प्रभारी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल • मध्यप्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। कई जिलों में पार्टी ने जिला प्रभारियों को बदला है। अंदरखाने की खबर है कि, काम न करने वाले जिला प्रभारियों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। जिला प्रभारी जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनके स्थान पर दूसरे नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पार्टी द्वारा किए बदलाव के अनुसार, इंदौर जिला प्रभारी रवि जोशी को भोपाल का प्रभारी बनाया गया है। ग्वालियर ग्रामीण प्रभारी संजीव सक्सेना को इंदौर का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं, ग्वालियर ग्रामीण संजीव सक्सेना को हटाकर पीसी शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। मंदसौर में जयवर्धन सिंह की जगह मनोज राजानी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयवर्धन सिंह गुना के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं इसलिए उन्हें जिला प्रभारी के प्रभार से हटाया गया है। जबकि, मुरैना में सिद्धार्थ कुशवाहा की जगह रामकिंकर गुजर प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं, पन्ना में संजय यादव की जगह यजमान सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। टीमकगढ़ से रेखा यादव की जगह राव यादवेंद्र सिंह की जिम्मेदारी दी गई है।
इन्हें भी मिली जिम्मेदारी-यही नहीं, जबलपुर में हरदा विधायक आर.के. दोगने की जगह राजकुमार खुराना को जिला प्रभारी बनाया गया है। निवाड़ी में राव यादवेंद्र सिंह के स्थान पर राम



नई कार्यकारिणी में इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की पुरानी प्रदेश कार्यकारिणी और सभी जिलाध्यक्षों को भंग कर दिया गया है। इसके बाद अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। नई कार्यकारिणी में प्रमुख नियुक्तियां इस प्रकार हैं-

- विभा पटेल - प्रदेश अध्यक्ष
- नूरी खान - कार्यकारी अध्यक्ष
- सुमिता मिश्रा - उपाध्यक्ष
- मनीषा रावत - उपाध्यक्ष
- सुनीता गावडे - पर्यवेक्षक

लखन दंडोतिया को कमान दी है। सतना में राजा बघेल की जगह सुनील सराफ को पद मिला है। सीधी में अजय टंडन को हटाकर दिलीप मिश्रा को नियुक्त किया गया है। उमरिया अनुभा मुंजारे की जगह नीरज बघेल जिला प्रभारी बनाये गए। जबलपुर शहर में हरदा

इसके अलावा 36 महासचिव भी नियुक्त किए गए हैं।
मंगलवार को प्रदेशाध्यक्ष जितू पटवारी की मौजूदगी में महिला कांग्रेस की पहली कार्यकारिणी बैठक हुई। बैठक में संगठन सुजन अभियान की शुरुआत की गई। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस और प्रदेश कमेटी मिलकर पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे, जो पूरे प्रदेश के जिलों का दौरा करेंगे। ये पर्यवेक्षक जिला स्तर पर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर नए जिलाध्यक्षों के लिए पैनल तैयार करेंगे।

विधायक आरके दोगने की जगह राजकुमार खुराना को जिम्मेदार दी गई। देवास विक्रान्त भूरिया की जगह सुरेंद्र सिंह शेर लेंगे। होशंगाबाद, ओम पटेल को बनाया सुखदेव पांसे। खंडवा में आरके दोगने और रीना बोरासी को जिम्मेदारी मिली है।

करवा चौथ के लिए सजे इंदौर के बाजार...



इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • पति को लंबी उम्र की कामना का पर्व करवा चौथ कल मनाया जाएगा। करवाचौथ के पर्व को लेकर इंदौर के मध्यक्षेत्र राजबाड़ा और उसके आसपास के बाजारों में मिट्टी के बने करवा, पूजन सामग्री की दुकानें भी सजी गई हैं। जहां मिट्टी के करवा 40 से 100 रुपए तक बिक रहे हैं। गौरतलब है कि करवा चौथ

को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह रहता है। अभी से महिलाएं तैयारी में जुटी हुई हैं। इस दौरान कपड़े, चूड़ी, पार्लर और ज्वेलर्स की दुकानों पर महिलाओं की ज्यादा भीड़ लग रही है। बाजारवाद के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक और ज्वेलरी कंपनियां भी लुभावने आफर के साथ करवा चौथ व्रत का फायदा उठाने के लिए जुट गई हैं।

टीआई सुसाइड केस में एसआई बर्खास्त

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • टीआई सुसाइड केस में मध्यप्रदेश शासन ने एसआई रंजना खोड़े को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभागीय जांच में सामने आया है कि खोड़े टीआई हाकिम सिंह को ब्लैकमेल कर रही थीं। इसे विभाग ने गंभीरता से लिया। जांच अधिकारी ने माना कि इससे पुलिस की छवि धूमिल हुई है। खोड़े बर्खास्तगी से पहले तक धार जिले में पदस्थ रही हैं। मामला सवा तीन साल पुराना है। जून 2022 में इंदौर के रिगल स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में टीआई हाकिमसिंह पंवार ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से पहले एसआई रंजना खोड़े पर गोली चलाई थी और फिर खुद को गोली मार ली थी। इस हमले में

रंजना बच गई थीं, क्योंकि गोली उनके कान के पास से निकल गई थी, जबकि पंवार की मौत हो गई थी। मामले की दो बार जांच कराई गई। पहली जांच एसआईटी ने की, जिसमें रंजना को दोषी पाया गया था और उनकी एक वेतनवृद्धि रोकी गई थी पर पुलिस कमिश्नर इस जांच से संतुष्ट नहीं थे। गोली से बाल-बाल बची एसआईटी ने टीआई के खिलाफ छोटी ग्वालटोली पुलिस से शिकायत की थी। इस प्रकरण में पुलिस ने मृत टीआई पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। इसके बाद टीआई हाकिमसिंह पंवार ने ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए थे, तब पुलिस ने ब्लैकमेलिंग की धाराओं में रंजना के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।

विकास का नया रोडमैप हुआ तैयार, 4 बड़े प्रोजेक्ट्स में खस्ताहाल हुए जिंसी हाट का भी होगा कायाकल्प

डेड करोड़ी हाट बाजार डेम को कोड़ी का कर दिया

नगर निगम का डेढ़ करोड़ में बना इतवारिया हाट डेम बना कचरा डीपिंग स्टेशन



आशीष शिंदे (96446-30000)

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • हाल ही में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में हुई इंदौर स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में नेहरू पार्क पुनर्विकास, जिंसी हाट बाजार और हेरिटेज डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
इंदौर को एक स्मार्ट और सुविकसित शहर बनाने की दिशा में कलेक्टर शिवम वर्मा की

अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में शहर के कई बड़े विकास कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई।
बैठक में इन प्रमुख विकास कार्यों पर हुई चर्चा के मुख्य केंद्र



में नेहरू पार्क और जिंसी हाट बाजार का पुनर्विकास, शहर की ऐतिहासिक धरोहरों का विकास (हेरिटेज डेवलपमेंट) और स्मार्ट सिटी की आय बढ़ाने के उपाय शामिल थे।
बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि विकास के सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए।
नगर पालिक निगम परिषद सम्मेलन आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ ही चन्दन नगर से कालानी नगर निकलने वाले रोड पर भी अहम चर्चा होगी-नगर पालिक निगम परिषद का सम्मेलन आज गुरुवार को अटल बिहारी बाजपेयी परिषद सभागृह अटल सदन निगम मुख्यालय, इंदौर में आयोजित किया गया है। सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही पार्षद अनवर कादरी की पार्षद पद से हटाए जाने वाले मुद्दे पर भी चर्चा होगी।

यौन अपराधों में एफआईआर के लिए आ रही परेशानी के लिए सरकार का निर्णय

अब थाने में महिला सब निरीक्षक की उपस्थिति हुई अनिवार्य

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल • सरकार महिलाओं से जुड़े अपराधों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई के दावे करती है, पर हकीकत उलट है। छेड़छाड़ और यौन शोषण जैसे मामलों में एफआईआर के लिए नाबालिग बच्चियों को भी थानों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। महिला संबंधी अपराधों की शिकायत सुनने से लेकर एफआईआर, मेडिकल और बयान लेने के हक महिला सब इंस्पेक्टर या उससे वरिष्ठ अधिकारी को ही है पर भोपाल कमिश्नरेट के 38 थानों में सिर्फ 31 महिला सब इंस्पेक्टर हैं। इनमें भी 5 मातृत्व या चाइल्ड केयर लोव पर हैं, जबकि 4 ऑफिस स्टाफ में हैं। फील्ड में 22 सब इंस्पेक्टर हैं। कई थानों में महिला



एसआई हैं ही नहीं। शिकायत मिलने पर कंट्रोल रूम से किसी अन्य थाने की महिला अफसर को बुलाया जाता है, जिससे एफआईआर दर्ज करने में 3 से 4 घंटे की देरी हो जाती है।
छेड़छाड़ की शिकायत, चार घंटे करना पड़ा इंतजार-अशोका गार्डन में छेड़छाड़ की शिकायत युवती 3 सितंबर की सुबह 11 बजे थाने पहुंची। वहां महिला सब इंस्पेक्टर नहीं थी। बाकी जगह भी सभी महिला एसआई किसी न किसी ड्यूटी पर थीं। अंत में मिसरोद थाने की

एसआई श्वेता शर्मा ड्यूटी पूरी कर 3.30 बजे अशोका गार्डन थाने पहुंची, फिर एफआईआर हुई।
एसआई को 5 घंटे लगे आने में, तब तक समझौता हो गया-दो महीने पहले, रात 9.30 बजे थाना गौतम नगर में दुष्कर्म की शिकायत लेकर आई महिला को 5 घंटे इंतजार करना पड़ा। रात्रि गश्त से लौटने के बाद एसआई रुपा मिश्रा थाने पहुंची, लेकिन पीड़िता ने रात 3.30 बजे कहा कि समझौता हो गया है और एफआईआर नहीं कराना चाहती।
अफसर भी मानते हैं- महिला सब इंस्पेक्टरों की कमी है-भोपाल में महिला संबंधी अपराधों को देखते हुए महिला सब इंस्पेक्टरों की कमी तो है। मौजूदा पदस्थ महिला एसआई में से कुछ लीव पर हैं। कुछ की लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी होती है। ऐसे में कई बार दिक्कत होती है।

सम्पादकीय

सड़कें सिर्फ गाड़ियों के लिए हैं
तया? पैदल यात्रियों का हक
आखिर कौन मानेगा?

भारत में हर साल हजारों पैदल यात्री सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी राज्यों को उनके लिए नियम बनाने का सख्त आदेश दिया है। सड़कों पर पैदल चलने वालों को सुरक्षा का उतना ही अधिकार है, जितना वाहनों में सवार लोगों का होता है। इस पर गौर करना जरूरी है कि सड़कें केवल वाहनों के लिए नहीं हैं, पैदल यात्रियों को भी उन पर चलने का हक है। यातायात नियम भी सभी पर लागू होते हैं। मगर सवाल है कि क्या पैदल यात्रियों को सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है? हर वर्ष सड़क हादसों में जान गंवाते वालों में बड़ी संख्या पैदल यात्रियों की होती है। यह सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा है। एक गहरी प्रणालीगत विफलता है। यही वजह है कि अब सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैदल यात्रियों तथा गैर-मोटर चालित वाहनों के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए छह माह की समय सीमा तय की गई है। हालांकि, कुछ राज्य इस दिशा में पहले ही कदम बढ़ा चुके हैं, लेकिन उनकी नियमावली या तो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है या फिर उन पर कड़ाई से अमल नहीं हो पा रहा है। देश में सड़क सुरक्षा की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों जारी एक रपट से लगाया जा सकता है। इसके मुताबिक, वर्ष 2023 में देश भर में 4.8 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं। इनमें से करीब 1.72 लाख लोगों की मौत हो गई और 4.62 लाख लोग घायल हुए। इन हादसों में जान गंवाते वालों में 68 फीसद पैदल यात्री और दोपहिया सवार शामिल थे। यह आंकड़ा बताता है कि सड़कों पर सबसे ज्यादा खतरा पैदल चलने वालों और दोपहिया चालकों को होता है। दरअसल, देश में ज्यादातर सड़कें मुख्य रूप से वाहनों को ध्यान में रख कर ही बनाई गई हैं, जिससे पैदल यात्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए जटिल जहद करनी पड़ती है। यह बात छिपी नहीं है कि अधिकांश शहरों में फुटपाथ या तो हैं ही नहीं या वे टूटे हुए हैं या फिर उन पर अतिक्रमण हो गया है। इस वजह से नागरिकों को मुख्य सड़कों पर चलने के लिए विवश होना पड़ता है, जहां तेज रफतार वाहनों से हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। सड़कों पर यातायात को सुचारु रूप से संचालित करने और सुरक्षा के लिए देश में मोटर वाहन अधिनियम बनाया गया है, मगर उसमें 'पैदल चलने के अधिकार' को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इस कारण पैदल यात्रियों को सुरक्षा को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस ने वर्ष 2012 में फुटपाथों को लेकर कई सुझाव दिए थे, जिनमें पैदल चलने के लिए कम से कम 1.8 मीटर चौड़ा और बाधा-मुक्त क्षेत्र बनाने का सुझाव भी शामिल था।

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद उठ रहे हैं अनेक प्रश्न

बिहार में ठीक एक महीने बाद दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होगा। मतलब साफ है कि अब सोचने का समय नहीं है। परिणाम चाहे जो भी आए मुख्य रूप से 7 फेक्टर्स की भूमिका कहीं न कहीं से रहेगी ही। 19 साल से ज्यादा समय से राज्य के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की अग्निपरीक्षा तो है ही। लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी को उनके मुद्दों पर जनता का कितना साथ मिलता है यह भी पता चल जाएगा।

बिहार चुनाव के पुराने समीकरण खंगाले जाय तो बिहार में जिस पार्टी को जातिगत समीकरण मिलता है, वह जीतती है, जैसा कि एनडीए में भाजपा और नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) ने पिछले दो दशकों में जीत हासिल की है। इस बार भी इस समीकरण पर भाजपा की पकड़ ढीली नहीं हुई है, इसलिए इस चुनाव ने भी उम्मीद के मुताबिक रफतार पकड़नी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया है कि इस बार एनडीए को अस्थिर करने वाले दो फैक्टर फायदा उठाएंगे या हिट होंगे।

बिहार में एक समय में तीन, पांच, सात चरणों में चुनाव होते थे, लेकिन इस बार सिर्फ दो चरणों में मतदान होगा। हैरानी की बात है कि भारत के चुनाव आयोग ने एक भी चरण में मतदान कराने की हिम्मत नहीं की है, जब देश में कहीं भी चुनाव नहीं होता है और सारी सुरक्षा एजेंसियां उपलब्ध हैं। अगर %एक राष्ट्र, एक चुनाव% की नीति लागू करनी है तो बिहार जैसे बड़े राज्य में एक ही चरण में चुनाव कराने की क्षमता आयोग के पास होनी चाहिए। मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, यानी छठ पूजा पूरी होने के बाद नौवें दिन पहला चरण और छठ पूजा संपन्न होने के 14वें दिन दूसरा चरण होगा। हाल के दिनों में वोट चोरी के आरोपों के साथ, बिहार में मतदान की तारीखें एक बार फिर आयोग को आरोपियों के पिंजरे में डाल सकती हैं। बिहार में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 11 घंटे तक मतदान होगा। किसी ने भी मतदान की अवधि पर आपत्ति नहीं जताई होगी। हालांकि, विपक्ष को संदेह है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान शाम पांच बजे के बाद मतदान प्रतिशत अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है, जिसके बाद मतदान का समय बदल दिया गया है। बिहार में एक पोलिंग बूथ पर 1200 मतदाता हैं। अगर हर मतदाता को एक मिनट भी लगता है, तो भी हर किसी को वोट डालने में 20 घंटे लगेंगे। मान लीजिए कि मतदान 100 प्रतिशत नहीं है, अगर शाम 5 बजे के बाद लंबी कतारें लगती हैं, तो महाराष्ट्र में विवाद दोहराया जाएगा।



गौरतलब है कि 74 वर्षीय मुख्यमंत्री की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही है, और यही विपक्षी महागठबंधन का मुख्य हथियार बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि अब नीतीश प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, और राज्य एक सात-आठ सदस्यीय राजनीतिज्ञों और अफसरों का समूह चला रहा है। तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अक्सर नीतीश कुमार के समारोहों के वीडियो साझा करते हैं ताकि यह दिखा सके कि सीएम अब उतने सक्रिय नहीं हैं। रविवार को पटना के एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार के बार-बार हाथ जोड़ने का का वीडियो इसका ताजा उदाहरण है।

हालांकि जेडीयू ने लगातार इन आरोपों का खंडन किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोमवार को कहा, वह (नीतीश) सभी फैसले खुद ले रहे हैं। उनकी सेहत सिर्फ विपक्ष का मुद्दा है। सहयोगी भाजपा भी बार-बार यह कह रही है कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़े जा रहे हैं। लेकिन भाजपा यह बताने से बच रही है कि चुनाव के बाद क्या होगा। जाहिर है कि नीतीश के प्रति बिहार में अब भी जो सम्मान है उसके चलते भाजपा इस मुद्दे पर फूंक फूक कर कदम रफ रही है। दरअसल डर यह है कि अगर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं हैं, यह बात आम लोगों तक पहुंच गया तो एनडीए के लिए स्थितिमां माकूल नहीं रह सकेगी।

एनडीए ने विरोधी लहर को रोकने के लिए नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से लगातार आम जनता की भलाई के लिए कोई न कोई फैसले ले रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं के लिए कई योजनाओं की झड़ी लगा दी है। अब तक 1.21 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये जा चुके हैं ताकि वे कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। यह वितरण मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जारी रहेगा क्योंकि आचार संहिता चल रही योजनाओं पर लागू नहीं होती। राज्य सरकार 1.89 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये प्रति माह किया गया है। जीविका, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। साथ ही 18 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को दो वर्षों तक प्रति माह 1,000 रुपये भत्ता देने की घोषणा की गई है।

उधर बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष सघन जांच अभियान को राहुल गांधी ने मुद्दा बना दिया। उनका साथ देने के लिए पूरा इंडिया गुट आधे अधूरे मन से लगा गया। बिहार में 17 अगस्त से लेकर एक सितंबर तक की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर यात्रा भी निकाली। दोनों नेताओं को देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ भी जुटी पर जिस तरह तेजस्वी ने दुबारा यात्रा निकाली है और वोट चोरी के मुद्दे पर अब उनका उतना फोकस नहीं है, उससे तो यही लगता है कि महागठबंधन यह समझ चुका है कि यह मुद्दा फुटस हो चुका है। मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप कितना काम किया इसका नीतीश 14 नवंबर को बिहार चुनाव परिणामों के साथ ही आ जाएंगे। दूसरी तरफ एनडीए ने एसआईआर के विरोध को घुसपैठियों को प्रोत्साहन देने वाला बताया है। चुनाव परिणाम से साबित करेगा आम लोगों को अपनी बात समझाने में कौन अधिक सफल रहा।

एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात बार-बार कहता तो है। पर चुनाव परिणाम आने के बाद उनके सीएम बनाने की बात पर भाजपा और जेडीयू दोनों ही ओर से एक तरह की चुप्पी ही है। दरअसल नीतीश की बिगड़ती सेहत को देखते हुए एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपनी मुख्य चेहरा बनाया हुआ है। जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में मोदी ने स्थानीय नेतृत्व के भरोसे ही चुनाव अभियान को छोड़ रखा था। पर बिहार में ऐसा नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह पूरे प्रदेश में प्रभाव दिखाते वाला भाजपा का कोई स्थानीय नेता

बिहार में नहीं है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के पास राज्यव्यापी जनअपील में वह प्रभाव नहीं है जो एनडीए को चाहिए। इसी तरह जनता दल यू में भी नीतीश कुमार ने कभी भी किसी को अपने डिप्टी के रूप में उभरने ही नहीं दिया। नीतीश कुमार जिस तरह बीमार दिख रहे हैं उसके चलते मोदी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जेडीयू के किसी भी नेता में राज्यव्यापी अपील नहीं है। जाहिर है कि सारा दारोमदर नरेंद्र मोदी पर ही है।

पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा रखी है। जन सुराज पार्टी (हुस्सू) के बारे में कहा जा रहा है कि एनडीए के लिए यह पार्टी बहुत घातक साबित होने वाली है। पिछले कुछ दिनों में भाजपा के शीर्ष नेताओं पर उनके आरोपों ने सत्तारूढ़ दल को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बारे में तो उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुंह छुपाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं बिहार की जातिगत राजनीति से ऊबे बहुत से लोगों के लिए किशोर का यह संदेश कि उनकी सरकार प्रवास, बेरोजगारी और सुशासन जैसे मुद्दों पर ध्यान देगी। जाहिर है कि बहुत से लोगों के लिए वो उम्मीद की किरण बन रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार ने अंतिम मौकों पर प्रोबोब की घोषणाएं की हैं उसके पीछे कहीं न कहीं प्रशांत किशोर ही हैं। जाहिर है कि अगर महागठबंधन को कई सीटों पर आड़ले मिलती है तो उसमें कहीं न कहीं प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज का भी हाथ होगा।

सवाल यह भी है कि एनडीए के लिए लालू प्रसाद यादव के जंगलराज का नैरेटिव बिहार विधानसभा चुनावों में क्या इस बार भी काम करेगा? दरअसल RJD की छवि को अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता से जोड़कर मतदाताओं में फाय पैदा कराना ही एनडीए के लिए एक बार फिर फायदेमंद साबित हो सकता है। 1990-2005 के लालू-राबड़ी काल को जंगलराज बताकर NND ने 2005, 2010, 2020 चुनावों में सफलता हासिल की, जहां अपहरण, हत्या और लूट की घटनाओं का जिक्र कर जनता को नीतीश कुमार के सुशासन से जोड़ा जाता रहा है।

पिछले कुछ समय से बिहार में अपराध बढ़ने से ह्यू पर सवाल उठे हैं। इसके साथ ही इस बार ऐसे युवाओं की मात्रा इस बार वोट देने वालों की अधिक है जिन्होंने जंगलराज में बारे में केवल सुना है। जाहिर है कि उनके लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हो सकता है कि उनके लिए जंगलराज का नैरेटिव कमजोर हो जाए।

अशोक भाटिया,

वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार

आंचलिक

1.30 लाख के पटाखे जब्त, पुलिस ने देवला में 8 कार्टून बरामद किए



खरगोन • दैनिक इंदौर संकेत

बिस्तान स्थित सरवर देवला में पुलिस ने बुधवार को अवैध पटाखा भंडारण पर कार्रवाई की। एक रहवासी मकान से 1 लाख 30 हजार 985 रुपए कीमत के पटाखे जब्त किए हैं। यह कार्रवाई दीपावली से पहले अवैध पटाखा संग्रहण के खिलाफ पुलिस के अभियान का हिस्सा है।

बिस्तान थाना पुलिस टीम को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर गिराई पिता रमेश श्रीमाली निवासी सरवर देवला के घर पर दबिश दी गई। पुलिस ने उनके रहवासी मकान

और दुकान के पीछे बने हिस्से से 8 कार्टून में बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद किए।

आरोपी गिराई श्रीमाली के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है।

खरगोन जिले में अवैध पटाखों के भंडारण पर यह तीसरी कार्रवाई है। इससे पहले सीतावल्लभ मार्केट और महेश्वर में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है।

सरपंच पति समेत दो लोग 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

लोकारुवत इंदौर ने पकड़ा, जमीन विवाद सुलझाने मांगे थे 25 लाख

खरगोन • दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन में लोकारुवत पुलिस ने बुधवार को छोटी कसरदाव ग्राम पंचायत के सरपंच पति और उनके एक साथी को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मंडलेश्वर रेस्ट हाउस में की गई।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सरपंच पति सुरजित सिंह राठौर और उनके साथी धर्मेश सिंह राठौर के रूप में हुई है।

इंदौर निवासी रिटायर्ड सैनिक अंतिम जैन ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी अंतिम जैन से कृषि भूमि के रास्ते के



एवज में कुल 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इसी मामले में आज एक लाख रुपए की पहली किश्त लेते हुए इंदौर लोकारुवत पुलिस ने कार्रवाई की।

महिला के शव से 'अश्लील हरकत' - डेढ़ साल दबाया मामला

युवक घसीटकर ले गया, फिर वापस रखा, केस दर्ज

बुरहानपुर • दैनिक इंदौर संकेत

डेढ़ साल पुराने महिला के शव से छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसने स्ट्रेचर पर रखे शव को छुआ। फिर उसे घसीटा हुआ ले गया। कुछ देर बाद वापस रख गया। पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामला खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का है। घटना 18 अप्रैल 2024 की सुबह के बीच हुई। खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया कि एक दिन पहले 7 अक्टूबर को डॉक्टर आद्या डावर ने खकनार थाने में इस मामले में शिकायत की थी। धारा 297 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर मामला जांच में लिया गया है। आरोपी को बुधवार दोपहर न्यायालय में पेश किया गया।

सीसीटीवी फुटेज में यह दिखा- सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सीएचसी के पोस्टमॉर्टम रूम के बाहर स्ट्रेचर पर महिला का शव रखा है। यहां एक युवक आता है। वह इधर-उधर देखता है। फिर महिला के शव की तरफ झुकता है। वापस इधर-उधर देखता है। फिर शव से छेड़छाड़ करने

लगता है। थोड़ी देर बाद उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। करीब एक हफ्ते पहले सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए टेक्निकल टीम को महिला के शव से छेड़छाड़ का वीडियो दिखा। उन्होंने प्रभारी बीएमओ आद्या डावर को जानकारी दी। मामला कलेक्टर हर्ष सिंह तक पहुंचा। उन्होंने एक समिति बनाकर जांच करने के आदेश दिए।

समिति ने वीडियो की सच्चाई जांची। घटनास्थल का वेरिफिकेशन कराया। अस्पताल का रिकॉर्ड खंगाला। मंगलवार को कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट सौंपी। घटना के बाद नर्सिंग स्टाफ भी घबरा गया था, लेकिन विभाग ने इस पूरे मामले को अब तक दबाए रखा। सीएमएचओ डॉ. आरके वर्मा ने कहा कि अब तक इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि इसे स्वास्थ्य विभाग को एक बड़ी चूक माना जा रहा है। यह पूरा घटनाक्रम 2024 में अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। बताया जा रहा है कि विभाग से ही सीसीटीवी फुटेज लीक होने के बाद यह मामला सामने आया।

खाद्य दुकानों से नमूने जांच को भोपाल भेजे, अमानक पाए जाने पर होगी कार्रवाई

बुरहानपुर • दैनिक इंदौर संकेत

कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर की कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं। ये नमूने जांच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजे गए हैं। यह कार्रवाई लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। बुधवार को हुई जांच के दौरान विशाल मेगा मार्ट (लालबाग रोड) से मखाने का नमूना लिया गया। वहीं, लक्ष्मी किराना (मंडी बाजार) से डालडा घी और गुलाब जामुन, सरस्वती दूध डेयरी (मंडी बाजार) से मावा और पनीर, संपूर्ण इंटरप्राइजेज (स्टेडियम ग्राउंड) से गुलाब जामुन, और गुरु ट्रेडर्स (स्टेडियम ग्राउंड) से चना दाल व बेसन के नमूने लिए गए। विभाग ने बताया कि अगर जांच में कोई नमूना अमानक पाया जाता है, तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विभाग ने कहा कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी जारी रहेगी।

मंडी में कपास की नीलामी पहले दिन 6200 रुपए की सबसे ऊंची बोली

खंडवा • दैनिक इंदौर संकेत

कृषि उपज मंडी समिति में आज बुधवार को कपास की नीलामी का शुभारंभ हुआ। नीलामी के पहले दिन श्रीगणेश में ही किसान गणेश यादव का कपास 6200 रुपए प्रति क्विंटल की उच्चतम बोली पर बिका। जिसे राधेश्याम हरिगोपाल फर्म ने खरीदा।

7 फर्म हुए शामिल- मंडी सचिव ओपी खेड़े ने बताया कि, नीलामी में कुल 7 फर्म अजीत एग्रो, अजय एग्रो, हनुमान जिनिंग फैक्ट्री, ज्योति इंडस्ट्रीज, राधेश्याम हरिगोपाल, संदीप इंडस्ट्रीज और वर्धमान कॉर्ट फाइबरस के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंडी में कुल 100 वाहनों में कपास की आवक हुई।

किसानों को मिला अच्छा दाम- कपास की नीलामी में किसानों को अच्छा दाम मिला। उच्चतम भाव 6901 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि न्यूनतम भाव 5550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मॉडल भाव 6401 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इधर, किसान संगठनों का मानना है



कि, इस बार कपास की फसल बिगड़ने से उत्पादन पर असर पड़ा है। कपास के रेट 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए।

ये व्यापारी और कर्मचारी रहे मौजूद- नीलामी के शुभारंभ अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य किसान और व्यापारी मौजूद रहे। जिनमें कैलाश बंसल, जितेंद्र सिंह उबेजा, मनोज राठौर, शांतनु डोंगरे, राजू घीया, मनीष घीया, संजय अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, मनोज शेटे और अशोक शर्मा शामिल थे। बोली की शुरुआत उद्घोषक प्रेमलाल खेडेकर और सहायक आनंदसिंह गौड़ ने की।

सीसीआई का नया नियम- जिले में ही बिकेगा कपास

बाहरी जिलों के किसानों पर लगी रोक, फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद

खंडवा • दैनिक इंदौर संकेत

भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने कपास खरीदी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर जिले के किसानों को अपनी कपास की उपज अपने ही जिले की मंडियों में बेचनी होगी। पड़ोसी जिलों के किसान अब यहां आकर कपास नहीं बेच पाएंगे। सीसीआई का कहना है कि इस नियम का मकसद कपास खरीदी में पारदर्शिता लाना और व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले फर्जीवाड़े को रोकना है।

3200 किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन-खंडवा जिले में कपास बेचने के लिए अब तक 3200 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें खंडवा के 2000 और मूंदी के 1200 किसान शामिल हैं।

बाहरी जिलों से 25% कपास आता था- पहले सीसीआई अपनी कुल खरीदी का 25% कपास बाहरी जिलों से खरीदता था। लेकिन अब इस नियम के लागू होने से बाहरी जिलों से कपास की खरीदी नहीं हो पाएगी।

वूमंस वर्ल्ड कप - आज जीत की हैट्रिक को उतरेगा भारत

विशाखापट्टनम (एजेंसी) • भारतीय टीम ने आईसीसी वूमंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में अपने पहले दो मुकाबले जीत लिए हैं। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी को तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ना है। हालांकि, भारतीय टीम के शीर्षक्रम के बल्लेबाजों को आत्मविश्वास से ओतप्रोत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी महिला विश्व कप के मैच में गुरुवार को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। भारत अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है। भारत ने भले ही पिछले दोनों मैच जीते हों, लेकिन स्मृति मंधाना, कसान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स के बल्लों से रन नहीं निकलना चिंता का विषय है। तीनों श्रीलंका के खिलाफ नाकाम रही थीं, जिसके बाद हरलीन देयोल, अमनजोत



कौर, रिचा घोष और दीप्ति शर्मा ने टीम को संकट से निकाला। श्रीलंका के खिलाफ भारत ने छह विकेट 124 रन पर और पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट 159 रन पर गंवा दिए थे। निचले क्रम के बल्लेबाजों का योगदान नहीं होता, तो भारत की स्थिति खराब हो सकती थी। हालांकि, दक्षिण

अफ्रीका के खिलाफ इस तरह की गलती नहीं की जा सकती और शीर्षक्रम के बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा। अगर नतीजा भारत के पक्ष में नहीं रहता, तो अंकतालिका में स्थिति खराब होने के अलावा पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले में भी टीम पर दबाव रहेगा। भारतीय टीम प्रबंधन सकारात्मक पहलू देखना चाहेगा कि स्टार बल्लेबाजों के नहीं चलने पर भी जीत टीम को गहराई को दिखाती है, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि मंधाना, हरमनप्रीत और जेमिमा का बल्ला दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गजों के खिलाफ खामोश रहा तो यह निर्णायक साबित हो सकता है।

इंदौर के तीन खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे

इंदौर संकेत प्रतिनिधि
इंदौर • इंदौर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तीन खिलाड़ी 40 वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। एसोसिएशन के सचिव गोवविन्दा चिंतामण ने बताया कि 40 वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 10 से 14 अक्टूबर तक भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में इंदौर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के मंथन काग 18 वर्ष आयु की 100 मी दौड़, दिशा तिवारी 16 वर्ष आयु की गोल फेंक तथा स्तुती जायसवाल 16 वर्ष की ही 200 मी दौड़ में मध्यप्रदेश की तरफ से भाग लेंगे इस प्रतियोगिता में देश के 700 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। खिलाड़ियों के चयन पर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी पिंटू शर्मिला तेजावत सचिन यादव पहलवान जितेंद्र गौड़ अपुर्व दुबे मिलन मांडलिक मनीष जरिया शुभम गौड़ दीपक यादव आदि ने हर्ष व्यक्त किया है।

धोनी मुंबई इंडियंस के लोको वाली टी शर्ट में नजर आये



मुंबई (एजेंसी) • चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) को पांच बार आईपीएल खिताब जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल 2026 में खेलने को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। हर बार बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके संन्यास की अटकलें लगायी जाती रही हैं पर धोनी मैदान में उतरकर सबको हैरान कर देते हैं। वहीं अब एक नई तस्वीर आई है। इसमें धोनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के लोको लगी ड्रेस में नजर आये। इसके बाद से

ही प्रशंसक अटकलें लगाने लगे कि धोनी कहीं मुंबई इंडियंस में तो नहीं जा रहे। इस तस्वीर में धोनी कुछ क्रिकेटर्स और कुछ प्रशंसक के साथ जो टी शर्ट पहने हुए हैं, उस पर मुंबई इंडियंस का लोगो लगा हुआ है। धोनी जैसे तो एक फुटबॉल गेम का हिस्सा बने थे पर क्रिकेट पर एमआई का लोगो देख हर कोई अटकलें लगाने लग गया है कि वे अगले सत्र में मुंबई इंडियंस की ओर से खेल सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रशंसक ने कहा कि रोहित शर्मा को चेन्नई शामिल करें।

सिने जगत

फिल्म 'हैवान' में नजर आएगी अक्षय-सैफ की जोड़ी



मुंबई (एजेंसी) • अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म हैवान में नेगेटिव किरदार निभाते नजर आएंगे। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की सुपरहिट जोड़ी फिल्म हैवान में साथ नजर आएगी। अक्षय और सैफ ने ये दिल्ली, में खिलाड़ी तू अनाड़ी, तू चोर में सिपाही, कीमत, आरजू और टशन जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। अब यह जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है। फिल्मकार प्रियदर्शन, अक्षय और सैफ की जोड़ी को फिर से साथ में ला रहे हैं। अक्षय और सैफ फिल्म हैवान में साथ दिखने वाले हैं हैवान एक हाई-ऑक्टेन थ्रिलर फिल्म है। इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। अक्षय कुमार ने फिल्म हैवान में अपने किरदार का खुलासा किया है। हाल ही में एक कार्यक्रम में अक्षय कुमार ने बताया है कि वह फिल्म हैवान में नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। अक्षय कुमार ने कार्यक्रम में कहा, 'मैं एक

मैं ब्रांड पर ज्यादा ध्यान नहीं देती - दिव्यांका त्रिपाठी

मुंबई (एजेंसी) • अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में अपने स्टाइल और सादगी से सभी का ध्यान खींच लिया। मुंबई में चल रहे इस इवेंट में उन्होंने न सिर्फ अपने लुक से सबका दिल जीता, बल्कि फैशन और ब्रांड्स को लेकर अपने बेबाक विचार भी साझा किए। दिव्यांका ने बताया कि वह ब्रांड्स को लेकर कभी जुनूनी नहीं रहतीं। उन्होंने कहा, मैं ब्रांड पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मैं वही चीज खरीदती हूँ जो मुझे पसंद आती है, चाहे वह किसी भी ब्रांड की हो। मेरे लिए सबसे जरूरी यह है कि वह चीज मुझे सूट करे और मेरे व्यक्तित्व के अनुरूप हो। फैशन की अपनी परिभाषा बताते हुए दिव्यांका ने कहा, मेरे लिए फैशन वह सब कुछ है जो आरामदायक हो। यह जरूरी नहीं कि वह महंगा या बहुत शानदार हो। अगर कोई आउटफिट आंखों को भाता है और पहनने में सहज लगता है, तो वही मेरे लिए फैशन है। जो चीजें आकर्षक होने के साथ आराम भी देती हैं, वही असली स्टाइल है। दिव्यांका त्रिपाठी अपने पारंपरिक लुक और ग्रेसफुल अंदाज के लिए जानी जाती हैं। सार्वजनिक आयोजनों में वह अक्सर भारतीय परिधानों में नजर आती हैं और हर बार अपने स्टाइल से फैसले को प्रभावित करती हैं।



ऐसी फिल्म कर रहा हूँ, जिसमें नेगेटिव रोल निभा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं। फिल्म का नाम 'हैवान' है। लेकिन अंत में मैं हार जाता हूँ। 'हैवान' हार जाता है।

उज्जैन संभाग

रील बनाने वाले युवक का सुसाइड-शव रखकर परिजन ने किया चक्काजाम



इंदौर संकेत प्रतिनिधि
उज्जैन • उज्जैन में सोशल मीडिया पर पुलिस को अपशब्द कहते हुए चैलेंज करने वाले युवक ने बुधवार सुबह फांसी लगा ली। इससे नाराज परिजन ने चिमनगंज मंडी चौराहे पर शव रखकर नारेबाजी कर चक्काजाम कर दिया। परिजन ने चिमनगंज पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने अभिषेक चौहान और उसके दोस्त विक्की राठौर को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद दोनों के माफ़ी मांगते हुए वीडियो भी सामने आए थे। जिसमें वे हाथ जोड़कर कहते दिखाई दे रहे थे कि अब से ऐसी हरकत नहीं करेंगे।

एक हफ्ते पहले पोस्ट किया था वीडियो

विराटनगर में रहने वाले अभिषेक चौहान ने अपने साथी विक्की राठौर के साथ इंस्टाग्राम पर करीब 1 हफ्ते पहले एक वीडियो पोस्ट किया था। जिसमें अभिषेक चौहान पुलिस को चैलेंज कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पर कार्रवाई करते हुए

दोनों को बंद कर दिया था। मंगलवार शाम को जमानत मिलने के बाद युवक अपने घर चला गया था। बुधवार सुबह उठने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभिषेक की आत्महत्या का पता चलते ही उसके परिजन ने मंडी गेट के बाहर चक्काजाम कर दिया। पुलिस पर रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को कार्यवाही की मांग की है। मामले की सूचना पर जीवाजीगंज और माधवनगर सीएसपी मौके पर पहुंचीं और परिजनों को समझाइश देकर चक्काजाम खुलवाया।

रील में कह- टूट चूका हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ

अभिषेक चौहान की मौत के मामले में भले ही परिजन पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हों, लेकिन पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग के कारण मौत होना बता रही है।

फर्जी डॉक्टर का ऑडियो, कहा- सेटलमेंट कर लो-मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा; बच्चे की मौत के बाद भी एफआईआर नहीं

इंदौर संकेत प्रतिनिधि
उज्जैन • उज्जैन में गलत इलाज से हुई बच्ची की मौत के मामले में अब तक जिम्मेदारों पर सख्तर नहीं हो सकी है। फर्जी डॉ. तैयबा के एक हफ्ते से अधिक समय बीत जाने के बाद भी खुलेआम घूम रही है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने माना है कि वो फर्जी ड्रिग्राधारक है, उसे डिलीवरी और इलाज करने की अनुमति नहीं है। अब पुलिस और स्वास्थ्य विभागों के आपसी तालमेल के नहीं होने के कारण उस पर सख्तर तक दर्ज नहीं हो पाई है। आरोपी फर्जी महिला डॉक्टर खुलेआम मृत बच्चे के परिजन को फोन पर आपस में बैठकर मामला निपटा लेने की धमकी भी दे रही है। महिला डॉक्टर का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वह बोल रही है कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बात आगे मत बढ़ाओ, बैठकर बात कर



लो। मामले में 3 अक्टूबर को अस्पताल में हुए हंगामे और फर्जी महिला डॉक्टर के अस्पताल को सील करने के बाद फर्जी

डॉ. तैयबा ने मृत बच्ची के मामा महेश मालवीय को फोन लगाकर सेटलमेंट करने की बात कही थी। जिसके बाद

परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ पंचासा थाने में आवेदन दिया, लेकिन अब तक उस पर सख्तर तक दर्ज नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग ने उसका अस्पताल सील करके पल्ला झाड़ लिया। मामले में जब डॉ. तैयबा शेख का पक्ष जानना चाहा तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था।

सीएमएचओ और पुलिस एक-दूसरे पर टाल रहे

डॉ. तैयबा शेख की ड्रिग्री फर्जी निकली है। इससे पहले भी एक बच्चे की मौत के मामले में उसका क्लिनिक सील हो चुका है। उस दौरान उस पर सख्तर दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी क्लिनिक सील की ही कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य अमला और पुलिस विभाग दोनों एक दूसरे पर सख्तर नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं।

आगर मालवा में किसानों का प्रदर्शन, हाईवे जाम-सोयाबीन के कम भाव पर मंडी में दो घंटे रुकी नीलामी

आगर - मालवा • दैनिक इंदौर संकेत
आगर मालवा में सोयाबीन के कम भाव मिलने से नाराज किसानों ने बुधवार को नेशनल हाईवे-52 जाम कर दिया। छावनी नाका चौराहा पर लगे इस जाम के कारण लगभग 30 मिनट तक यातायात बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही एसडीएम मिलिंद ढोके, सीएसपी मोतीलाल कुशवाह और थाना प्रभारी सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने किसानों से चर्चा की, उनकी समस्याएं सुनीं और एसडीएम किसानों के साथ पैदल मंडी पहुंचे। इसके बाद हाईवे पर लगा जाम खोला गया और पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों से यातायात सुचारु कराया। मंडी पहुंचने पर किसानों ने नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी और सोयाबीन के कम भाव मिलने को लेकर मंडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप था कि व्यापारियों द्वारा सोयाबीन का भाव मात्र 3000 प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, जबकि उनकी मांग है कि भाव 5000 प्रति क्विंटल किया जाए, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। किसानों ने यह भी शिकायत की कि एक ही फसल पर मशीन से जांच में अलग-अलग परिणाम आने से व्यापारी इसका लाभ उठा रहे हैं। वहीं,



व्यापारियों ने बताया कि प्लांटों पर भाव कम होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं और जिले के चार प्लांटों में दरों में अंतर होने से असमानता बनी हुई है। त्वचा के दौरान एसडीएम ढोके ने निर्देश दिए कि एक जैसे माल पर अलग-अलग भाव नहीं आने चाहिए। उन्होंने स्वयं मौके पर मशीन से जांच कर अंतर देखा। एसडीएम ने घोषणा की कि अब से मंडी समिति की नमी जांच मशीन का ही उपयोग किया जाएगा और नीलामी के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजस्व विभाग के दो कर्मचारी तैनात रहेंगे। इन निर्देशों के बाद करीब दो घंटे बाद मंडी की नीलामी प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकी और स्थिति सामान्य हुई।

सविदा शिक्षक पर छात्राओं से अमद्रता का आरोप, अभावित ने बर्खास्तगी और एफआईआर दर्ज करने की मांग

आगर - मालवा • दैनिक इंदौर संकेत

आगर मालवा में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ एक सविदा शिक्षक शकील अंसारी पर छात्राओं के साथ अश्लील और अमर्यादित व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जापन सौंपा और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अभावित पदाधिकारियों ने प्रशासन को सौंपे जापन में बताया कि शिक्षक शकील अंसारी पिछले कई दिनों से विद्यालय की छात्राओं के साथ आपत्तिजनक हरकतें कर रहे थे। अभावित ने जिला प्रशासन से मांग की है कि

ऐसे शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर सेवा से बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही उसके खिलाफ आपराधिक केस (एफआईआर) दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। परिषद ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही आरोपी शिक्षक के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो संतुलन छात्राओं की मर्यादा को रक्षा के लिए उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगा। इस घटना के सामने आने के बाद विद्यालय की छात्राओं और उनके अभिभावकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं जिला प्रशासन ने इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की बात कही है। मांग की जांच के बाद आरोपी की कार्रवाई होने की संभावना है।

27 फीसदी ओबीसी आरक्षण केस हाईकोर्ट में फिर से मामला भेजने की उठी बात

एमवाय अस्पताल प्रशासन का छलावा उजागर निलंबित डॉ. को दी गई जिम्मेदारी, कोर्ट और जनता दोनों को गुमराह किया

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • एम.वाय. अस्पताल प्रशासन की बड़ी कार्रवाई का पर्दाफाश हो गया है। जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट लोकेश मुजाल्दा ने बताया कि चूहा कांड में दिखावे के तौर पर की गई निलंबन कार्यवाही अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। प्रशासन ने चूहा कांड के बाद डॉ. मुकेश जायसवाल, सहायक अधीक्षक को निलंबित बताया था, लेकिन अब वही अधिकारी दवाई, गोली और अन्य चिकित्सा सामग्री की खरीदी समिति के सदस्य बना दिए गए हैं। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि एम.वाय. प्रशासन की कार्रवाई केवल दिखावा थी और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया।

एम.वाय. अस्पताल के डीन और अधीक्षक ने माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर यह दावा किया था कि उन्होंने दोषियों पर बड़ी कार्रवाई की है, और प्रमाण स्वरूप उसी दस्तावेज में डॉ. जायसवाल के निलंबन आदेश को प्रस्तुत किया था। लेकिन अब उसी अधिकारी को परचेजिंग कमेटी में शामिल कर देना न्यायालय, जनता और मीडिया - तीनों को भ्रमित करने का गंभीर अपराध है। यह कदम एमवाय प्रशासन की भ्रष्ट मानसिकता और मिलीभगत को उजागर करता है। जयस संगठन शुरू से यह कहता आया है कि एम.वाय. अस्पताल के डीन और अधीक्षक लगातार झूठ बोल रहे हैं, जनता, जिला प्रशासन, मीडिया और पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने झूठ को खुद ही साबित कर दिया है। जिस अधिकारी को निलंबित बताया गया था, उसे पुनः समिति में शामिल करना न केवल प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि यह चूहा कांड जैसी दर्दनाक घटना को दबाने का सुनियोजित प्रयास भी है।

कल होगी सुनवाई, शासन ने समय मांगा



वहीं यह बात भी अधिवक्ताओं ने इस मुद्दे पर रखी कि ट्रांसफर याचिकाएं हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं। हाईकोर्ट ने इसमें अंतरिम आदेश दिए हुए हैं। इसलिए मामला यहां आया है। वहीं छत्तीसगढ़ में दी गई अंतरिम राहत की भी बात कही गई। इस पर यह पक्ष भी रखा गया कि वहां यह अंतरिम राहत इसलिए दी गई क्योंकि कुछ भर्ती प्रक्रिया चालू थी और वह पूरी होने तक के लिए ही राहत दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मराठा मामला, बिहार मामला हो या राजस्थान का मामला हो वहां नहीं दिया है।

ओबीसी वेलफेयर के अधिवक्ताओं ने ये कहा

ओबीसी वेलफेयर कमेटी की ओर से अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने कहा कि आज सुनवाई थी लेकिन मद्र सरकार ने फिर समय मांगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति ली और कहा कि फिर दिवाली छुट्टी आ जाएगी। हमारे पास अन्य अहम केस भी हैं, तो वर्यो ना इसे आप हाईकोर्ट में ही ले जाए, बार-बार आप समय मांग रहे हैं। हम इसे अगले सप्ताह नहीं सुनेंगे, कल रखा जाएगा। अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि फिर सरकार ने समय मांगा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। यह भी कहा कि मद्र की भौगोलिक, जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इस आरक्षण के कानून को जो एमपी सरकार द्वारा बनाया गया है। इसे हाईकोर्ट डिसाइड करे। ठाकुर ने कहा कि हाल ही में तेलंगाना मामले में भी यही कहा कि आरक्षण को लेकर स्टेट हाईकोर्ट डिसाइड करे।

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • मद्र की राजनीति के सबसे बड़े 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की होने वाली अहम सुनवाई के दौरान पहले ही शासन ने एक दिन का समय मांग लिया। सांलिंसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसे कल 9 अक्टूबर को सुना जाए तो बेहतर होगा। लेकिन इसी दौरान पांच मिनट तक विविध अधिवक्ताओं ने बात रखी और अहम मुद्दा उठाया। मेहता ने इसमें बार-बार अगले दिन (नौ अक्टूबर) की सुनवाई की बात रखी, जबकि अन्य पक्ष सुनवाई के लिए इसमें तैयार थे।

क्यों ना हाईकोर्ट में फिर भेजा जाए केस-इस मामले में यह बात सुप्रीम कोर्ट बेंच की ओर से ही उठी कि क्यों ना मुद्दे को फिर एमपी हाईकोर्ट भेजा जाए। बेंच ने कहा कि क्योंकि आरक्षण पूरी तरह से राज्य से जुड़ा मामला है, वहां की टोपोग्राफी क्या है, जनसंख्या क्या है, क्या स्थानीय मुद्दे हैं, यह इन सभी से लिंक है और इस पर राज्य हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है।

कैलाश विजयवर्गीय के भावांतर योजना पर नए वादे से उलझी मोहन सरकार

सराफा चौपाटी : दीपावली बाद ही होगी निर्णायक बैठक

60 दुकानों पर सहमति, अभी लग रही दो सौ से ज्यादा दुकानें

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • सराफा चौपाटी की दुकानों को लेकर निर्णायक बैठक का इंतजार सराफा एसोसिएशन और चौपाटी एसोसिएशन दोनों पदाधिकारी कर रहे हैं। त्यौहारी सीजन में सराफा में दीपावली की चमक-दमक रहना है, ऐसे में दोनों खेमों को लगता है कि चौपाटी का फैसला दीप पर्व के बाद ही होगा। फैसला लेना है त्रिपक्षीय समिति को, फिलहाल तो सराफा चौपाटी वाली दो सौ से अधिक दुकानें लग रही हैं, सराफा एसोसिएशन का साफ कहना है हम तो 60 दुकानों के पक्ष में हैं, इतनी दुकानें तो नहीं लगने देंगे।

महापौर के साथ सोना-चांदी व्यापारी और चौपाटी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को संयुक्त बैठक के बाद तय हुआ था कि गठित की गई समिति नए सिरे से



बड़ा-छोटा सराफा का अवलोकन करेंगे, आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करेंगे, समय निर्धारण के साथ दोनों एसोसिएशन के सुझाव सुनेंगे।

चांदी-सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष हुकम सोनी ने बताया हम तो महापौर के साथ निर्णायक बैठक का इंतजार कर रहे हैं। अपने सदस्य व्यापारियों को स्पष्ट कह रखा है चौपाटी दुकान को लेकर

कोई नया किराया अनुबंध नहीं करेंगे। अभी तो उतनी ही दुकानें लग रही हैं लेकिन निर्णायक बैठक में हमारा एजेंडा रहेगा कि चौपाटी के लिये अधिकतम 60-65 दुकानों को ही अनुमति दी जाए। हमारा यह भी सुझाव रहेगा कि जिन 60-65 दुकानों पर सहमति बने तो वो सारी दुकानें भी रोड के एक तरफ ही लगे, अभी रोड के दोनों किनारों पर लग रही हैं।

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोयाबीन खरीदी के लिए आई एमपी सरकार की भावांतर योजना पर एक वादे ने सीएम डॉ. मोहन यादव की सरकार को उलझा दिया है। मंत्री भावांतर योजना के लिए निकाली गई धन्यवाद रैली पर दशहरा मैदान पर बोल रहे थे। उधर बीजेपी द्वारा 7 अक्टूबर को की गई धन्यवाद रैली के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा भावांतर योजना के विरोध में 8 अक्टूबर बुधवार को ट्रेक्टर रैली कर रहा है और साथ ही वह इंदौर-उज्जैन के बीच ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का भी विरोध कर रहा है।

मंत्री विजयवर्गीय ने इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को पहले घेरा और कहा कि वह बहुत झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की भी हद होती है कोई सिर-पैर तो होता है ना, वह भी

ग्रीनफील्ड रोड और भावांतर विरोध में ट्रैक्टर रैली



नहीं है। वह कहते हैं कि किसान भाईयों की उपज 3000 में बिक जाएगी, उग रही है सरकार। मंत्री ने आगे कहा कि मैं दावे से कह रहा हूँ इस जवाबदार मंच से यदि किसी किसान का 3000 में सोयाबीन बिका तो 2028 रुपए मोहन सरकार उसके खाते में डालने का काम करेंगी यह है भावांतर योजना। हमारे किसी किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, यह बीजेपी सरकार की इच्छा है। अब इसमें उन्हें क्या तकलीफ है। भावांतर योजना के तहत यह होना है कि 24 अक्टूबर से पहले 15 दिन तक मंडियों में बिके सोयाबीन का औसत भाव लेकर मॉडल रेट निकाला जाएगा।



और फिर मॉडल रेट और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) जो 5328 रुपए तय है के बीच का अंतर किसान के खाते में जाएगा। जैसे मॉडल रेट 4500 रुपए तय हुआ और किसान का सोयाबीन 4800 में बिका तो किसान के खाते में एमएसपी और उपज बिकने के मूल्य 4800 के अंतर का 528 रुपए मिलेगा। यदि किसान का सोयाबीन 4000 रुपए में बिका तो उसे मॉडल रेट 4500 और एमएसपी के बीच का अंतर यानी 828 रुपए खाते में मिलेगा। यानि मंत्रीजी जो कह रहे हैं कि सोयाबीन 3000 में बिका तो दो हजार मोहन सरकार देगी यह भावांतर योजना में नहीं आता है।

किसान को मॉडल रेट और एमएसपी के बीच का अंतर ही मिलेगा। उधर एमपी में बीजेपी सरकार की इस भावांतर योजना के तहत अभी पंजीयन काम ही चल रहा है। वहीं इंदौर में इसके लिए सरकार को धन्यवाद रैली निकल गई। जबकि उधर किसान संघ इसका विरोध कर रहा है और वह एमएसपी मांग रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक जीतू जिराती व अन्य नेताओं ने जब इसके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली तो जमकर ट्रोल हुए। किसानों ने कहा कि अभी तो योजना में खरीदी शुरू नहीं हुई, ना राशि मिलना फिर किस बात की धन्यवाद रैली। इस ट्रेक्टर रैली में प्रति ग्रामीण विधानसभा से 300 ट्रेक्टर लाने की बात थी लेकिन कुल ट्रेक्टर ही 300 से कम पहुंचे।

जन्मदिन की पार्टी में पहुंचे युवक की बदमाशों ने चाकू घोंपकर हत्या की

भगवानों की मूर्तियों पर थूकने से भड़के बजरंगी, दी चेतावनी

पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर के घर लोकायुक्त का छापा भोपाल में जेपी मेहरा के घर पहुंची टीम, भ्रष्टाचार के लगे आरोप

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • विजय नगर इलाके की स्क्रीम नंबर 54 स्थित वाइन शॉप के बाहर एक युवक की हत्या हो गई। बताया जा रहा है मृतक पार्थ दीवान (19) निवासी नंदा नगर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में शराब पीने वाइन शॉप के बाहर पहुंचा था। शराब पीने के दौरान उसका कुछ बदमाशों से विवाद हुआ। थोड़ी देर बाद बदमाश अपने साथियों के साथ आए और पार्थ के सीने पर चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।

जानकारी के अनुसार मृतक पार्थ दीवान अपने दोस्त चिराग की बर्थडे पार्टी में करीब 4-5 दोस्तों के साथ स्क्रीम नंबर 54 की वाइन शॉप के बाहर बने अवैध अहाते में शराब पीने पहुंचा था। शराब पार्टी के दौरान उसका पास से निकल रहे 4-5 युवकों

से कहासुनी हुई थी। दोनों पक्षों में मामूली विवाद हुआ जिसके बाद सभी युवक निकल गए। थोड़ी देर बाद बदमाश हथियार लेकर पहुंचे और पार्थ पर हमला करने का प्रयास किया। वह भागा लेकिन करीब 50 मीटर की दूरी पर एक्टिवा से आए तीन बदमाशों ने पार्थ पर जानलेवा हमला कर दिया। उसके सीने में जमकर चाकू मारे और भाग निकले। मौके पर लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। सूचना पर विजय नगर एसीपी, विजय नगर थाना प्रभारी सीके पटेल सहित अन्य पुलिसकर्मी जांच करने पहुंचे थे। मामले में पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। जल्द ही आरोपी गिरफ्त में आ सकते हैं। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें बदमाश पार्थ के साथ मारपीट कर चाकू से वार कर रहे हैं।

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के एमटीएच कंपाउंड में लगाए गए देवी-देवताओं के टाइल्स पर लोगों द्वारा थूकने की शिकायत पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क उठे। बजरंग दल सुभाष प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सेंट्रल कोतवाली थाने पहुंचकर इस संबंध में आवेदन दिया और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि कंपाउंड नगर निगम के अधीन है और यहां लगाए गए टाइल्स पर भगवानों के चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों के पास गंदगी फैलाना और थूकना हिंदू भावनाओं का अपमान है। बजरंग दल के जिला सह-



संयोजक ईश्वर प्रजापत ने कहा कि यह क्षेत्र महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सनातनी विधायक गोलू शुक्ला के कार्यक्षेत्र में आता है। यदि 24 घंटे के भीतर वहां से भगवानों की तस्वीरें नहीं हटाई गईं तो बजरंग दल उग्र आंदोलन

करेगा। साथ ही, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे, उनका मुंह काला कर तस्वीरें वहीं लगाई जाएंगी, उन्होंने चेतावनी दी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारिका जिले के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल • भोपाल में पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के पूर्व चीफ इंजीनियर जेपी मेहरा के भोपाल स्थित मणिपुरम आवास पर गुरुवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के तहत की गई है। जेपी मेहरा पर अपने कार्यकाल के दौरान विभागीय टेकों और निर्माण कार्यों में गड़बड़ियों के आरोप हैं। इन्हें आरोपों की जांच करते हुए लोकायुक्त की टीम आज सुबह पुलिस बल के साथ उनके घर पहुंची और तलाशी शुरू की।

केस और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज मिले

जानकारी के अनुसार, छापे के दौरान लोकायुक्त की टीम को बड़ी संख्या में केस और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। इनमें मुंबई में खरीदी गई संपत्ति से जुड़े प्रमाण भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह छापे गोपनीय सूचना के आधार पर मारा गया है। मेहरा इसी साल फरवरी में रिटायर हुए थे। फिलहाल मणिपुरम स्थित उनके आवास में लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है।

व्हिस्पेरिंग पॉम्स में अवैध निर्माण का मामला कोर्ट पहुंचा

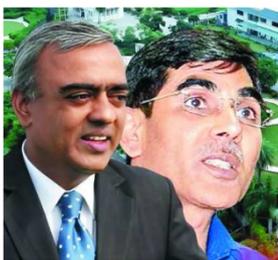
पूर्व सीएस एसआर मोहंती और राधेश्याम जुलानिया को नोटिस

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • भोपाल की वीवीआईपी कॉलोनी व्हिस्पेरिंग पॉम्स में अवैध निर्माण का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। पूर्व सीएस, बड़े अफसरों और बड़े व्यापारियों की इस कॉलोनी में कई तरह की अनियमितताएं बरतने के आरोप हैं। इतना ही नहीं भोपाल विकास योजना 2005 के खुलेआम उल्लंघन और कलियासोत बांध के जलग्रहण क्षेत्र में अनुमत सीमा से कई गुना अधिक निर्माण होने का आरोप भी लगाया गया है।

महेश सिंह परिहार और राज बहादुर प्रसाद ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जिसमें Bhopal Development Plan 2005 के खुले

उल्लंघन और कलियासोत बांध के जलग्रहण क्षेत्र में अनुमत सीमा से कई गुना अधिक निर्माण होने का आरोप है। बता दें कि कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं। इस केस को सुनवाई 24 नवंबर को होगी। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में कोर्ट की सख्ती को देखते हुए यह चर्चा तेज हो गई है कि व्हिस्पेरिंग पॉम्स पर भी बुलडोजर चल सकता है। हालांकि, फैसला आने में समय लग सकता है। याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट हर्षवर्धन तिवारी और एडवोकेट राहुल दिवाकर ने बताया कि हाईकोर्ट से व्हिस्पेरिंग पॉम्स भोपाल में अवैध निर्माण रोकने, विस्तृत सर्वे कराए जाने और



नियमों का उल्लंघन करने वाले ढांचों को ध्वस्त करने की मांग की गई है। बता दें कि कॉलोनी को कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया गया था, लेकिन यहां एक अवैध शॉपिंग

सेंटर समेत भारी निर्माण किया गया और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति की अवधि भी खत्म हो चुकी है।

नियमों को धता बताती- व्हिस्पेरिंग पॉम्स कॉलोनी-अतिविशिष्ट कॉलोनियों में शुमार व्हिस्पेरिंग पॉम्स कॉलोनी निर्माण भोपाल के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, कलियासोत बांध के जलग्रहण क्षेत्र के पास हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि डेवलपर्स और निवासियों ने शहर के विकास के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण नियमों को जमकर तोड़ा है। इससे पर्यावरण और आसपास के निवासियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। याचिका में सबसे बड़ा आरोप यह है कि व्हिस्पेरिंग

5 प्वाइंट में समझे पूरा मामला...

- महेश सिंह परिहार और राज बहादुर प्रसाद ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है।
- वे भोपाल की व्हिस्पेरिंग पॉम्स कॉलोनी में हो रहे कथित अवैध निर्माण को चुनौती दे रहे हैं।
- आरोप है कि भोपाल विकास योजना 2005 और नियमों का उल्लंघन कर अनुमत सीमा से आठ गुना अधिक निर्माण किया गया है।
- यह VVP कॉलोनी भोपाल के कलियासोत डैम के कैचमेंट एरिया के पास है, जिसमें कई अफसरों और व्यापारियों की कोठियां हैं।
- कॉलोनी को कम घनत्व आवासीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया गया था, लेकिन यहां भारी निर्माण और अवैध शॉपिंग सेंटर बनाया गया, जबकि अनुमति की अवधि भी खत्म हो चुकी है।

पॉम्स में नियमों का घोर उल्लंघन किया गया है। जहां विकास योजना के अनुसार भूखंड के केवल 6% हिस्से पर निर्माण की अनुमति थी, वहीं याचिका के अनुसार, कुछ निवासियों और डेवलपर्स

ने भूखंडों के 50% से अधिक हिस्से पर निर्माण कर लिया है। यह एप्रूव्ड सीमा से आठ गुना अधिक है, जो एक मामूली चूक नहीं, बल्कि नियमों का एक बड़ा उल्लंघन है।